नेताओं तथा अन्य वर्गों के लोगों को रेलगाड़ी में सफर करने के लिये जारी किये गये निःशुल्क रेलवे पासों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किये गये पासों के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये शिकायतें मुख्यतः पास की वैधता तिथि में रद्दोबदल करने/सहयोगी के रूप में यात्रा करने वाले व्यक्ति से पैसे लेने से संबंधित हैं ।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

633. श्री. यशवीर महेन्द्र खान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खाद्य वस्तुओं के क्या नाम हैं, जिनकी इस समय देश में कमी है और यह कमी कितनी मात्रा में है और उनकी कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन खाद्य वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है, उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इन वस्तुओं का आयात किये जाने की संभावना है और उनकी लागत कितनी है ;

(ग) भविष्य में खाद्य वस्तुओं की कमी न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) उन खाद्य वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिन्हें हम देश में सप्लाई करने में असमर्थ हैं और उन निर्यात की जाने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनके निर्यात की मात्रा कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम लखन पटेर) : (क), (ख) और (घ) मोटे तौर पर स्थिति यह है कि देश में दालें और खाद्य तेल ऐसी प्रमुख खाद्य वस्तुयें हैं जिनकी कमी है । इन वस्तुओं की वास्तविक कमी और यदि इन वस्तुओं का कोई आयात किया जाना है, तो उस दशा में उनकी मात्रायें देश में उनके उत्पादन पर निर्भर करते हुये वर्ष-प्रति-वर्ष भिन्न-भिन्न होती है ।

अंगोला को सहायता के रूप में दिये जाने वाले परस्पर सहमत 200 मीटरी टन चावल के निर्यात को छोड़कर फिलहाल सरकारी खाते पर गेहूं अथवा चावल का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । देश में जिन खाद्य वस्तुओं की कमी है उनका निर्यात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) खाद्य वस्तुओं की कमी को केवल उत्पादन में वृद्धि कर दर किया जा सकता है । खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये खरीफ 1988, से विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया गया है जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ चना और अरहर को भी शामिल किया गया है । कृषि पैदावार में वृद्धि करने के लिये छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन उथले नलकूपों/खातकूपों का निर्माण करने का कार्य 1990–91 में भी जारी रखा जायेगा ताकि विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वाले राज्यों के चुनिंदा जिलों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में अधिक उपज और पैदावार की क्षमता वाले क्षेत्रों में आवश्यक सुविधायें मुहैया की जा सकें ।

जहां तक तिलहनों का संबंध है, विभिन्न प्रकार के तिलहनों के उत्पादन और उपज में वृद्धि करने के लिये प्रमुख तिलहन/उत्पादक राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो परियोजनायें अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन प्रतिबल परियोजना लाई जा रही है ।